

संपादकीय जी-20 में अफ्रीकी संघ

राजधानी दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत ने कुछ अभूतपूर्व, वैश्विक और कूटनीतिक सफलताएं हासिल की हैं। सम्मेलन की शुरूआत के बाद 10 मिनट में ही प्रधानमंत्री मोदी ने 'अफ्रीकी संघ' को जी-20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करा लिया। यही नहीं, संघ के अध्यक्ष अजाली असीमानी को अपना स्थान ग्रहण करने को आमंत्रित भी किया। वह आए और प्रधानमंत्री मोदी से गले मिले और फिर स्थान ग्रहण किया। यकीनन यह ऐसा क्रांतिकारी निर्णय था कि एक साथ 55 अफ्रीकी देश झूम उठे होंगे, क्रांतिकारी हाशिए से उठकर वैश्विक मुद्दोंधारा का विचार तभी कर सकेंगे। अतएव यहां बिल्कुल है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'अफ्रीकी संघ' को जी-20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पारित करा लिया। यही नहीं, संघ के अध्यक्ष अजाली असौमानी को अपना स्थान ग्रहण करने को आमंत्रित भी किया। वह आए और प्रधानमंत्री मोदी से गले मिले और फिर स्थान ग्रहण किया। यकीनन यह ऐसा क्रांतिकारी निर्णय था कि एक साथ 55 अफ्रीकी देश झूम उठे होंगे, जोकी हाशिए से उठकर वैशिक मुख्यधारा का हिस्सा बनने का उन्हें अवसर मिला है। अब तीसरी दुनिया अथवा ग्लोबल साउथ का एक हिस्सा विश्व की विकसित तथा सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों से जुड़ेगा। ज्यादातर अफ्रीकी देश गरीब, पिछड़े, बीमार, कुपोषित और भुखमरी के शिकार रहे हैं। कुछ देश आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन कोरोना महामारी ने बहुत कुछ ध्वस्त कर दिया। चीन ने इन देशों की दुरावस्था का नाजायज फायदा उठाया है। हालांकि उसका निवेश 300 अरब डॉलर से अधिक का है। वह 9 अफ्रीकी देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी मदद कर रहा है। करीब 10 हजार कंपनियां अलग-अलग अफ्रीकी देशों में कार्यरत हैं, लेकिन अफ्रीकी देश महसूस करते हैं कि वे चीन के कार्ज तले दबे हैं, लिहाजा उससे मुक्ति चाहते हैं। भारत उनके लिए 'देवदूत' सावित हो सकता है। वैसे भी भारत अफ्रीकी देशों में 197 परियोजनाएं सम्पन्न कर चुका है। अब भी भारत की 182 से अधिक परियोजनाएं जारी हैं। अफ्रीकी देशों के 25,000 से ज्यादा छात्र भारत में पढ़ते हैं। हमने 12 अरब डॉलर का कार्ज बेहद कम ब्याज दरों पर अफ्रीकी देशों को मुहैया कराया है। भारत ने कोरोना महामारी के टीके, जेनेरिक दवाइयां, खाद्य सामग्री आदि भी उपलब्ध कराई हैं और हम अफ्रीकी शहरों को कंट्रोल

वह 9 अफ्रीका का दशा के अंतरक्ष कार्यक्रम में भी मदद कर रहा है। करीब 10 हजार कंपनियां अलग-अलग अफ्रीकी देशों में कार्यरत हैं, लेकिन अफ्रीकी देश महसूस करते हैं कि वे चीन के कर्ज तले दबे हैं, लिहाजा उससे मुकित चाहते हैं। भारत उनके लिए 'देवदूत' साबित हो सकता है। वैसे भी भारत अफ्रीकी देशों में 197 परियोजनाएं सम्पन्न कर चुका है। अब भी भारत की 182 से अधिक परियोजनाएं जारी हैं। अफ्रीकी देशों के 25,000 से ज्यादा छात्र भारत में पढ़ते हैं। हमने 12 अखर डॉलर का कर्ज बेहद कम ब्याज दरों पर अफ्रीकी देशों को मुहेय कराया है।

यह है कि भारत, अमरीका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यानी यूरोप के बीच समुद्री हजार और रेलगाड़ी का 'आर्थिक समुद्धि कॉरिंडोर' बनाने पर भी सहमति बनी है। यह अभूतपूर्व और वेमिसाल गलियारा होगा और इसके देशों के बीच कारोबार, आवाजारी, परिवहन आदि को ऐसे पंख लायेंगे, जिनकी कल्पना ही की जा सकती है। चीन-पाकिस्तान वाला गलियारा तो नाकाम हो चुका। वैसे भारत रूस और ईरान वाले कॉरिंडोर का भी हिस्सा है, लेकिन प्रस्तावित गलियारा उससे अलग और बड़ा विस्तृत होगा। तीसरी उपलब्धि यह रही कि भारत 37 पन्नों के 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' पर 100 फीसदी सहमतियां बनाने में कामयाब रहा। अटकले लगाई जा रही थीं कि घोषणा-पत्र जारी होने में मुश्किलें आएंगी, लेकिन भारत ने युद्ध और यूक्रेन का जिक्र भी किया। यूक्रेन का उल्लेख 4 बार किया गया है, लेकिन रूस का नाम नहीं लिया गया। भारत को यह समझौता जरूर करना पड़ा। कहा गया कि युद्ध के असर बड़े व्यापक होते हैं, लिहाजा यह युद्ध का युग नहीं है। परमाणु हथियारों की धमकी या उनका इस्तेमाल भी अस्वीकार्य है। किसी भी देश की संप्रभुता, अखंडता पर बल-प्रयोग न किया जाए। सभी देशों को यूएन चार्टर के मूलविक काम करना चाहिए। भारत घोषणा-पत्र में वैश्वक आतंकवाद का 9 बार जिक्र करने में कामयाब रहा। प्रस्ताव पारित किया गया कि आतंकवाद के हर रूप की निंदा करते हैं, क्योंकि यह शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। इनके अलावा, जी-20 ने सतत विकास, पर्यावरण, जैव ईंधन गठबंधन, डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अपनी प्राथमिकियां तय कीं।

ੴ ਅਤਿਥੀ

अब साशल माडिया का आपदा
की आपदा ने प्रक तया मनोविज्ञान सोच का आधार और

हमाचल का जन्मपुरा हमाना नाम प्राप्त है, जो आज तक उत्तर वक्तव्य को सहेजने की दिक्कारा पैदा की है। कुछ पात्र बदले हैं और इरादे भी पर्वतीय अंचल में उठे विनाश को दरकिनार करने की तरकीब में शीर्षासन कर रहे हैं। हिमाचल में यूं तो आज तक हुआ बहुत, मगर पाया क्या। तरकी के गुलगुले छानते-छानते हमने रेते के महल में महफिल सजा दी। कमोंबेश हर सरकार ने सियासी टोने टोटके किए, विकास के लक्ष्य और मंजिलें आकाश की तरफ उठा दीं। तीव्रग्रामी सरकारों ने पहाड़ पर इतने आंकड़े लाद दिए कि यह बोझलिए, सदी ने अपने प्रश्न बदल दिए। इसी आपदा में सोशल मीडिया का संसार गाली गलौज करने पर उत्तर आया या उसे भ्रम हो गया कि अब पृथ्वी पर उसकी बुद्धि ही अपराजेय होगी। सोशल मीडिया की इसी लड़ाई के योद्धा से पूछा जाए कि उसका योगदान क्या है, तो बगलें झाँकेगा, लेकिन कहने को दोष की अंगुलियां पहन कर हर इशारा करेगा। शिमला ही की बात करें, तो निर्माण के भूत तो हम ही निकलेंगे। इसमें दो राय नहीं कि प्रशासनिक ढीले के चलते सारे कायदे कानून ढीले हो गए, तो सामाजिक और सियासी व्यवस्था ने यह जुर्म साझा करके इसे नए हिमाचल की पहचान बना दिया। शिमला में बसने का दबाव सियासी और समाज से आया जहां अफसरशाही तथा नौकरशाही ने हाथ धो लिए। हिमाचल में पेड़ और पेट का रिश्ता आज तक समझा नहीं गया। पहले पेड़ और पेट आपस में मैत्रीभाव रखते थे। अब पेट कहता है पेड़ उखाड़ो। हमारी जीवनशैली यूं तो पेड़ से उखड़ गई, लेकिन हमने यह जिह्द भी नहीं की कि पर्वतीय होने के मायने क्या हैं। क्या हमने सेब आधिकी से जमीन के पानी और आबोहवा की निगरानी को विचलित नहीं किया। क्या हमने वन संरक्षण के नाम पर ऐसे पेड़ नहीं उगाए, जो केवल आंकड़ों में उग-उग कर चीड़ हो गए और जंगल कभी वन्य प्राणियों के बहाने, तो कभी आग के मुहाने तक बस्ती में उत्तर आया। पर्वतीय वास्तुकला के हिसाब से क्या भवन खड़ा करना मुमकिन है। जरा सोचें उस हिसाब से क्या इमारती लकड़ी मिल जाएगी, जो हमारी दीवारों और छत को पूरा कर देगी। क्या हमें खड़ु-नदी के प्रथर पर्वतीय निर्माण की कला में नींव को सुढ़व करने को मिल जाएगी। जरा बाजार में खड़ा होकर पूछना कि वहां तिलाजनन जींस परे पानी लाए आवाहिन तक तीव्रता से आयी।

क्लाइमेट थिंकटैक 'क्लाइमेट ट्रेंड्स' ने 'क्लाइमेट डॉट' के साथ मिलकर आज 'ईवी डैशबोर्ड' जारी किया।

इस डैशबोर्ड पर मिलेंगे देश की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सभी आंकड़े

निशान्त

देश के बाहन बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (इवा) को पैठत
लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्लाइमेट थिंकटैक
'क्लाइमेट ट्रैडेस' ने 'क्लाइमेट डॉट' के साथ मिलकर आज
'ईवी डैशबोर्ड' जारी किया। क्लाइमेट ट्रैडेस की निदेशक
आरती खोसला ने इसको जारी करते हुए कहा की – यहां
अनेकों डैशबोर्ड सरकार के 'वाहन' पोर्टल की मदद से
इलेक्ट्रिक वाहनों की विक्री से सम्बन्धित रियल टाइम डेटाएं
लेकर उसे बेहद आसान और उपयोगकर्ता के लिये
सुविधाजनक तरीके से पेश करता है जिससे बाजार में इलेक्ट्रिक
वाहनों की पैठ समेत विभिन्न स्तरों के बारे में त्वरित विश्लेषण
और शोध किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत
में राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर वर्षीय नीतियों को
उपभोक्ताओं के प्रति और मित्रवत बनाने तथा इस सिलसिले में
एक नियामक कार्ययोजना लागू करने की पूरी गुंजाइश है। देश
में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीतियाँ और उनकी प्रभावशीलता को
समझाने के लिये ईवी विक्री विश्लेषण की आवश्यकता तथा
अन्य पहलुओं पर विचार के लिये एक वेबिनार आयोजित किया
गया। क्लाइमेट डॉट के निदेशक अखिलेश मागल ने ईवी
डैशबोर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि इस टूल के जरिये हमने
इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी के क्षेत्र में मौजूद खामियों को ढूँढ़ने पर
ध्यान दिया है। इस डैशबोर्ड के जरिए उपयोगकर्ताओं को एक
ऐसा मंच देने की कोशिश की गयी है जहां वे अपनी बात को
बहुत प्रभावशाली तरीके से रख सकें। हालांकि अभी यह
डैशबोर्ड का पहला संस्करण ही है। भविष्य में इसे और बेहतर
बनाने की कोशिश की जाएगी। यह डैशबोर्ड सिर्फ शोधकर्ताओं
और अध्ययनकर्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि उन पत्रकारों के
लिए भी ही जो इस पर कोई लेख लिखना चाहते हैं, इसलिए हमने
यह सुनिश्चित किया है कि जो भी डाटा डैशबोर्ड पर डाल जाए
वह विलुक्त सटीक हो। हमारा यह भी उद्देश्य है कि पब्लिक
नैरेटिव भी बना रहे क्योंकि किसी भी तरह का रूपांतरण करने में
जन नियम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लाइमेट डॉट के
अंकित भृत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल डैशबोर्ड के बारे में विस्तार से
बताते हुए कहा कि इस डैश बोर्ड में सबसे पहले भारत में
इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के बारे में बताया गया है। इन वाहनों
को चार श्रेणियाँ में बांटा गया है। इनमें सूख्यतः दो पहिया वाहन,
तिपहिया वाहन, चार पहिया वाहन और बसें शामिल हैं। इसमें

महगाइ नियत्रण का काठन चुनात

यकानन्

यकानन पर लिए खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बीच इस समय सऊदी अरब और रूस द्वारा कच्चे तेल उत्पादन में कटौती के निर्णय से कच्चे तेल की कीमतें पिछले 10 माह के उच्चतम स्तर लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचने से महंगाई की चुनौती और कठिन हो गई है। ऐसे में सरकार के लिए महंगाई कम करना बड़ा मुद्दा बन गया है। यद्यपि केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाकर बड़ी राहत दी है, लेकिन आम आदमी सरकार से खाद्य पदार्थों की कीमतों के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल के दामों में कुछ कमी की भी अपेक्षा कर रहा है। हाल ही में 5 सितंबर को रिजव बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जुलाई 2023 में जो मुद्रास्फीति सप्लाई चेन के झटकों के कारण ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, उसे कम करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। गैरतलब है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अनुसार जून 2023 में जो खुदरा महंगाई दर 4.87 फीसदी थी, वह माह जुलाई में 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण खुदरा महंगाई दर केंद्र सरकार के 6 प्रतिशत की तय ऊपरी सीमा से अधिक है। आरबीआई ने चारों वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खुदरा महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 5.4 फीसदी कर दिया है। इस समय खाद्य कीमतों में तेज बढ़ोतारी के कई कारण

के साथ आर्थिक विकास भी प्रभावी और टमटारों की बढ़ी हुई कीमतोंने देख चुके हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर पर अंकुश लगाने वाला एक गवर्नर उपायों के साथ आगे आने के दामों में पिछले 15 माह में गिरावट दाम जस के तस बने हुए हैं। इन 2 करीब 110 डॉलर प्रति बैरल थी, हैं। साथ ही भारत की पेट्रोल-डीजल घरेलू कीमत घटाने की स्थिति में गिरावट पेट्रोल व डीजल पर सीमा व रेत सरकारी द्वारा वैट में कमी के कदम हैं। देश में जमाखोरी करने वालों जानी होगी। खाद्य पदार्थों के थोक भी उपयुक्त भंडारण सीमा लैंगूल नकदी की निकासी पर रिजर्व बैंक आवश्यक खाद्य पदार्थों के उपयुक्त से मजबूत आरूपित से खाद्य पदार्थ निर्यतित किया जाना होगा। साथ उपभोक्ताओं तक रियायती मूल्य आरूपित सुनिश्चित की जानी होगी। करने के लिए रूस से छत्ती पर 30

दिव्यांग

शैक्षणिक व्यवस्था का सूत्रधार है शिक्षक

मनुष्य की मानसिक शक्ति अत्यधिक विकसित है। मनुष्य के पास प्रचर

मात्रा में ज्ञान होता है। इस ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में लगाना चाहिए। तभी मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। मनुष्य कौन है? इस बात का उसे अध्ययन करना चाहिए और इस बात के लिए सदैव उसे प्रयासरत रहना चाहिए की वह कौन है? उसका अस्तित्व क्या है? यदि संतजनों की मानेतो मनुष्य वह है जो इस संसार को धर्मशाला समझे और अपने आपको उसमें ठहरा हुआ यानी। इस प्रकार कर्म करते हुए वह कर्म के बंधनों में न ही बंधेगा और न ही उसमें विकार भाव उत्पन्न होंगे। ज्ञान रूपी स्तम्भ जीवन को गति और सही दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। ज्ञान गुरुओं के द्वारा दिया जाता है। गुरु के बिना कोई भी समाज शिक्षित नहीं हो सकता है। मकान व स्तम्भ दोनों का आधार गुरु है। कहने का तात्पर्य बिना गुरु के ज्ञान वा कोई अधिकार नहीं। उचित धर्मिता के साथें सेवा

मनुष्यों की पहचान यह है कि वह साहित्य, संगीत, कला का आनंद लेना जानता हो। यदि दिन हीं जानले वह बिना पूँछ-सींग का साक्षात पशु है। भारत संस्कृति एक सतत संगीत है। आधुनिक काल मनुष्य अपने ज्ञान का दुरूपयोग कर रहा है। उसे अपनी सभ्यता व प्राचीन संस्कृति को खो दिया शिक्षा देने वाले को शिक्षक (अध्यापक) कहते हैं। शिक्षक के द्वारा व्यक्ति के भविष्य को बनाया जाए एवं शिक्षक ही वह सुधार लाने वाला व्यक्ति होते प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार शिक्षक स्थान भगवान से ही ऊँचा माना जाता है क्योंकि शिक्षक ही हमें सही या गलत के मार्ग का चयन कर सिखाता है। संत कबीर दास का एक दोहा है—
गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागू पाय। बलिहारी
आपने, गोविन्द दियो बताय। अर्थ—कबीर दास
ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है जिसमें विनीत में कर्मी देखी परिवर्तित होती है।

वीरों की जब गुरु और गोविन्द (ईश्वर) एक साथ खड़े मिलें तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। गुरु ने ही गोविन्द से हमारा परिचय कराया है इसलिए गुरु का स्थान गोविन्द से भी छंचा है। एक शिष्यक को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है जैसे- टीचर, अध्यापक, गुरु, आचार्य, आदि। गुरु जान का प्रतीक होता है। महान संत कबीर ने कहा था - कबीर ते नर अँध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर।। अर्थ - वे लोग अंधे हैं जो गुरु को ईश्वर से अलग समझते हैं। अगर भगवान रूठ जाएं तो गुरु का आश्रय है पर अगर गुरु रूठ गए तो कहीं शरण नहीं मिलेगा। शिक्षा (एन्युकेशन) बालक की जनन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित व प्रगतिशील विकास है। “शिक्षा व्यक्ति का ऐसा पूरी विकास है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से मानव जीवन के लिये अपनी गैरिकृत अधिकार प्राप्त कर सके ॥” चीन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य बहुत नेट-शृंखला के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करना और बाकी दुनिया के लिए प्रौद्योगिकी और घटना आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण सुरक्षित करना है। चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धी भयंकर है, हर कोई हरियां औद्योगिक युग में नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हालांकि प्रभावशाली विनिर्माण क्षमताओं और नवीकरणीय ऊर्जा में पर्याप्त निवेश द्वारा समर्थित, चीन ने विश्वेषण किए गए अधिकांश क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से बढ़ते ली है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि सभी पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं संबंधित समाजिक-आर्थिक लाभों को पहचानते हुए सक्रिय रूप से इस नए औद्योगिक युग में खुद को स्थापित करने का कोशिश कर रही हैं। रिन्यूबल एनर्जी, वैट्रैटर इलेक्ट्रिक वाहनों और हींग पंपों में विनिर्माण और निवेश को प्रौद्योगिकी डौड़ में सबसे आगे रह वाले देशों के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ के रूप में पहचाना जाता है। जबविं यूरोपीय संघ अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से डीकार्बोनाइज कर रहा और संयुक्त राज्य अमेरिका अनुसंधान और विकास निवेश के माध्यम से नवाचार में उत्कृष्ट प्राप्त कर रहा है, जापान भी नवाचार में एक मजबूत परिवर्तनी के जलवायन परिवर्तन आधार पर।

